आर.एन.आई. पंजीयन क्र. 39596/82 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)

साप्ताहिक

मालव अँचल

वर्ष 48 अंक 05 (प्रति रविवार) इंदौर, 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2024 पृष्ठ-8 मूल्य 3 रुपये

ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में प्रधानमंत्री मोदी ने कहा

भारत, युद्ध नहीं बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है

नई दिल्ली। *प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में कहा कि भारत युद्ध नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थन करता है। उन्होंने रूस-यूक्रेन संघर्ष को शांतिपूर्ण वार्ता के माध्यम से हल करने का आह्वान करते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया।*

हम युद्ध नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति के समर्थक-उन्होंने कहा, हम युद्ध नहीं, बल्कि संवाद और कूटनीति का समर्थन करते हैं। और जिस तरह हम कोविड जैसी चुनौती से मिलकर पार पा सके, उसी तरह हम निश्चित रूप से भावी पीढ़ियों के लिए सुरक्षित, मजबूत और समृद्ध भविष्य सुनिश्चित करने के लिए नए अवसर पैदा करने में सक्षम हैं। उल्लेखनीय है कि ब्रिक्स शिखर सम्मेलन में रूसी राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन और उनके चीनी समकक्ष शी जिनपिंग समेत ब्रिक्स देशों के शीर्ष नेताओं ने भाग लिया।

पीएम ने आतंकवाद से निपटने का किया आह्वान-इस दौरान प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने आतंकवाद से निपटने के लिए ठोस वैश्विक प्रयासों की भी वकालत की और कहा कि इस खतरे से लड़ने में कोई दोहरा मापदंड नहीं होना चाहिए। आतंकवाद और आतंकी वित्तपोषण का मुकाबला करने के लिए हमें सभी के एकजुट और दृढ़ समर्थन की आवश्यकता है। इस गंभीर मामले में दोहरे मानदंडों के लिए कोई जगह नहीं है। हमें अपने देशों में युवाओं के कट्टरपंथीकरण को रोकने के लिए सक्रिय कदम उठाने की आवश्यकता है। उन्होंने कहा, हमें संयुक्त राष्ट्र में अंतर्राष्ट्रीय आतंकवाद पर व्यापक सम्मेलन के लंबे समय से लंबित मामले पर मिलकर काम करना चाहिए। साइबर सुरक्षा-पीएम मोदी ने कहा, इसी तरह, हमें साइबर सुरक्षा और सुरक्षित एआई के लिए वैश्विक नियमों पर काम करने की जरूरत है। ब्रिक्स में नए देशों के स्वागत के लिए भारत तैयार-इस दौरान पीएम ने कहा कि भारत भागीदार देशों के रूप में ब्रिक्स में नए देशों का स्वागत करने के लिए तैयार है। उन्होंने कहा, इस संबंध में, सभी निर्णय आम सहमति से लिए जाने चाहिए और ब्रिक्स के संस्थापक सदस्यों के विचारों का सम्मान किया जाना चाहिए। पीएम मोदी ने कहा, जोहान्सबर्ग शिखर सम्मेलन के दौरान अपनाए गए मार्गदर्शक सिद्धांतों, मानकों, मानदंडों और प्रक्रियाओं का सभी सदस्यों और भागीदार देशों की तरफ से अनुपालन किया जाना चाहिए।

प्रधानमंत्री ने इस दौरान संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद और अन्य वैश्विक निकायों में सुधार की भी वकालत की। उन्होंने कहा, हमें संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद, बहुपक्षीय विकास बैंकों और विश्व व्यापार संगठन जैसे वैश्विक संस्थानों में सुधारों पर समयबद्ध तरीके से आगे बढ़ना चाहिए। जब हम ब्रिक्स में अपने प्रयासों को आगे बढ़ाते हैं, तो हमें यह सुनिश्चित करने के लिए सावधान रहना चाहिए कि यह संगठन वैश्विक संस्थानों की जगह लेने की कोशिश करने वाले संगठन की छवि न बना ले।

सभी 9 सीटों पर सपा के सिंबल पर लड़ेंगे गठबंधन के प्रत्याशी, उपचुनाव को लेकर अखिलेश का ऐलान

नई दिल्ली। यूपी की 9 विधानसभा सीटों पर होने वाले उपचुनाव को लेकर सपा-कांग्रेस में सीट शेयरिंग को लेकर मामला उलझता ही जा रहा है. इसी बीच बुधवार देर रात सपा प्रमुख अखिलेश यादव ने एक बड़ा दावा किया है. अखिलेश यादव ने सोशल मीडिया पोस्ट में कहा कि सभी 9 सीटों पर इंडिया गठबंधन के उम्मीदवार सपा के पार्टी सिंबल साइकिल पर चुनाव लड़ेंगे. अखिलेश यादव ने पोस्ट में कहा, 'बात सीट की नहीं जीत की है' इस रणनीति के तहत 'इंडिया गठबंधन' के संयुक्त प्रत्याशी सभी 9 सीटों पर समाजवादी पार्टी के चुनाव चिन्ह 'साइकिल' के निशान पर चुनाव लड़ेंगे. कांग्रेस और समाजवादी पार्टी एक बड़ी जीत के लिए एकजुट होकर, कंधे से कंधा मिलाकर साथ खड़ी है. इंडिया गठबंधन इस उपचुनाव में, जीत का एक नया अध्याय लिखने जा रहा है. कांग्रेस पार्टी के शीर्ष नेतृत्व से लेकर बूथ स्तर तक के कार्यकर्ताओं के साथ आने से समाजवादी पार्टी की शक्ति कई गुना बढ़ गयी है. इस अभूतपूर्व सहयोग और समर्थन से सभी 9 विधानसभा सीटों पर 'इंडिया गठबंधन' का एक-एक कार्यकर्ता जीत का संकल्प लेकर नयी ऊर्जा से भर गया है. उन्होंने आगे लिखा, ये देश का संविधान, सौहार्द और PDA का मान-सम्मान बचाने का चुनाव है. इसीलिए हमारी सबसे अपील है = एक भी वोट न घटने पाए, एक भी वोट न बँटने पाए. देशहित में 'इंडिया गठबंधन' की सद्भाव भरी ये एकता और एकजुटता आज भी नया इतिहास लिखेगी और कल भी.

विधानसभा उपचुनाव:13 राज्यों की 47 सीटें कई दिग्गजों के भविष्य का करेंगी फैसला

रांची। देश के 13 राज्यों में विधानसभा की 47 सीटों पर उपचुनाव होना है। ये वो सीटें हैं जिनमें से अधिकांश सीटें विधायकों के सांसद चुने जाने के कारण रिक्त हुई हैं। बिहार में 4, उत्तर प्रदेश में 10 और पश्चिम बंगाल में 6 सीटें शामिल हैं। बिहार, बंगाल और उत्तर प्रदेश में उपचुनाव की अहमियत बढ़ गई है, खासकर लोकसभा चुनाव में भाजपा की अपेक्षित सफलता नहीं मिलने के कारण। ममता बनर्जी की टीएमसी ने बंगाल में भाजपा को नुकसान पहुंचाया, वहीं उत्तर प्रदेश मैं समाजवादी पार्टी के नेतृत्व वाले विपक्ष ने भी भाजपा के खिलाफ प्रभावी रणनीति अपनाई।

बिहार में भाजपा को 5 सीटों का नुकसान हुआ, जबकि एनडीए की सहयोगी जेडीयू की भी 4 सीटें कम हुईं। तेजस्वी यादव, जो पिछले विधानसभा चुनाव में अपने बूते विपक्षी गठबंधन के विधायकों की संख्या 110 तक ले गए थे, उपचुनाव को अपनी प्रतिष्ठा बनाए रखने

के लिए एक अवसर के रूप में देख रहे हैं। जबकि, मुख्यमंत्री नीतीश कुमार अपने विकास कार्यों पर भरोसा रखते हैं। बिहार में अगले साल यानी 2025 में विधानसभा का पूर्णकालिक चुनाव होना है, जबकि पश्चिम बंगाल में 2026 और उत्तर प्रदेश में 2027 में चुनाव होंगे। इन उपचुनावों को महत्वपूर्ण इसलिए माना जा रहा है क्योंकि लोकसभा चुनाव में भाजपा की स्थिति कमजोर रही है। इन नतीजों को सेमीफाइनल के रूप में देखा जा रहा है, जिसमें सीएम योगी, ममता बनर्जी, तेजस्वी यादव और प्रशांत किशोर की प्रतिष्ठा दांव पर है। पश्चिम बंगाल में टीएमसी ने भाजपा को भारी नुकसान पहुंचाया है, और भाजपा को अपनी खोई जमीन वापस पाने के लिए चुनौतियों का सामना करना होगा। ममता बनर्जी को भी कई मुद्दों पर जवाब देना होगा, जिसमें भ्रष्टाचार और महिला अत्याचार के खिलाफ बने माहौल को लेकर भाजपा द्वारा उठाए गए सवाल शामिल हैं। इस प्रकार, उपचुनाव सभी राजनीतिक दलों के लिए अग्निपरीक्षा साबित होने वाले हैं, और नतीजे आगामी विधानसभा चुनावों की दिशा तय करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाएंगे। प्रशांत किशोर की पार्टी जन सुराज भी इस समय एक नया सियासी ध्रुव बनकर उभरी है। उन्होंने बिहार में बदलाव का माहौल तैयार करने के लिए कई नए चेहरे मैदान में उतारे हैं, जिसमें सेना के रिटायर्ड जेनरल एसके सिंह का नाम भी शामिल है। उत्तर प्रदेश भाजपा ने उम्मीदवार चयन में खुली छूट दी है और अंतर्कलह को खत्म करने की कोशिश कर रही है।

संपादकीय

दिखावे और गैर? जरूरी खर्च से बचें बचत पर? ध्यान दें

आज के दौर में दिखावे पर खर्च करना निम्न और मध्यम वर्ग में बड़ी तेजी के साथ बढ़ गया है। दिखावे के लिए कर्ज लेकर खर्च करने की प्रवृत्ति बड़ी तेजी के साथ बढ़ी है। पिछले कुछ वर्षों में गैर जरूरी खर्च लोग दिखावे के लिए कर रहे हैं। हवाई जहाज और ट्रेनों में आसानी से टिकट उपलब्ध नहीं हो रहे हैं। मध्यवर्ग के लोग हैसियत नहीं होने के बाद भी हवाई यात्रा कर रहे हैं। रेलवे में एसी पर यात्रा करना आज-कल दिखावे के रूप में निम्न मध्यमवर्गीय परिवारों में किया जा रहा है। यात्रा के दौरान टिकट से कई गुना ज्यादा पैसा ब्रांडेड सामग्री को खरीदने और खाने-पीने की चीजों में खर्च किया जा रहा है। एयरपोर्ट में कई गुने दामों में बिकने वाले सामान पर काफी पैसा खर्च किया जा रहा है। निम्न एवं मध्यम वर्ग के बीच में ब्रांडेड महंगी चीजों पर खर्च करना स्टेटस सिंबल बन गया है। वह भी उनके सामने जिन्हें वह जानते भी नहीं हैं। सोचने वाली बात है, कि इस तरह की फिजूलखर्ची के पीछे युवा वर्ग बड़ी तेजी से पैसे खर्च कर रहा है। छोटी-छोटी बचत से बड़ी रकम को बचाया जा सकता है। ऑनलाइन खरीदी की लत युवा वर्ग को बड़ी तेजी के साथ लगती चली जा रही है। मोबाइल फोन पर नई-नई चीज देखकर उन्हें खरीदने की आदत युवा वर्ग में नशे की तरह बढ़ती चली जा रही है। ऑनलाइन खरीदे गए सामान उनके लिए कितने उपयोगी हैं, कितने गैरजरूरी हैं, इसकी समझ भी उन्हें नहीं है। सबसे बड़े आश्चर्य की बात यह है कि कर्ज लेकर खर्च करना आज-कल के युवाओं का स्टेटस सिंबल बन गया है। आज की युवा पीढ़ी यह भूल गई कि उनके अपने परिवार के बुजुर्ग अपने समय में हमेशा जरूरत की चीजों पर ध्यान केंद्रित करते थे। वही चीज खरीदते थे, जो उनके लिए उपयोगी और जरूरी होती थीं। खर्चे में वो कभी कोई कमी नहीं करते थे, लेकिन जरुरत के लिहाज से ही खरीदी होती थी। बगैर जरुरत की चीजों में पैसा नहीं फेंका जाता था। अपनी आय के अनुरूप जरूरी खर्चों के बाद बचत करने पर विशेष रूप से ध्यान देते थे। यही नहीं हमारे बुजुर्ग कभी भी किसी के सामने अपनी आर्थिक स्थिति का भान होने नहीं देते थे। इन सब बातों के विपरीत आज का युवा वर्ग दिखावे की मानसिकता के चलते खर्चों पर नियंत्रण नहीं रख पाते हैं। बजाय इसके युवा वर्ग को प्राथमिकता के अनुसार ही खर्च करना चाहिए। दिखावे के लिए ब्रांडेड महंगे प्रोडक्ट्स खरीदने से हमारी सामाजिक स्थिति में कोई परिवर्तन नहीं आता है। उल्टे आज का युवा वर्ग कर्ज के जाल में फंसता जा रहा है। स्टेटस सिंबल को लेकर वह मानसिक रूप से हमेशा परेशान रहता है। युवाओं में बचत करने की कोई प्रवृत्ति नहीं है। आय और व्यय के बीच में संतुलन नहीं होने से बचत नहीं होती और इस कारण जब आकस्मिक कोई जरुरी खर्च करने की परिस्थिति सामने आती है तब यह युवा वर्ग बहुत परेशान हो जाता है। ऐसे में उसे कुछ सूझता नहीं है और कर्ज पर कर्ज लेकर अपनी जरुरतों को पूरा करने पर विवश हो जाता है। ऐसा करने से उसकी आगे की जिंदगी भी परेशानी में उलझती चली जाती है। नेक सलाह तो यही है कि गैरजरुरी खर्चों से युवा पीढ़ी को बचना चाहिए और बचत की ओर विशेष ध्यान देना चाहिए। युवाओं को यह नहीं भूलना चाहिए कि स्टेटस सिंबल के चक्कर में किए जाने वाले खर्च से चंद मिनट तो सुख मिल सकता है, लेकिन लंबे समय के लिए यह किसी काम का नहीं होता है। इसलिए इससे बचना चाहिए और हर बात को स्टेटस सिंबल से जोड़कर नहीं देखा जाना चाहिए। युवा मध्यम वर्ग और निम्न वर्ग को स्टेटस सिंबल को लेकर एक क्षणिक संतोष तो हो सकता है, लेकिन इससे आगे फिर उनको परेशानी और मानसिक प्रताड़ना का शिकार होना पड़ता है। युवाओं के साथ ही निम्न एवं मध्यम वर्गीय परिवारों को यह समझने की जरूरत है।

बांग्लादेश में हिन्दूओं पर अत्याचार, सख्त कार्रवाई की दरकार

ललित गर्ग

बांग्लादेश में हिंदू मंदिरों एवं हिन्दुओं पर हो रहे हमलें, मशहूर जेशोश्वरी मंदिर में मुकुट का चोरी होना, हिन्दू अल्पसंख्यकों से जबरन इस्तीफा के लिये दबाव बनाने की घटनाएं, दुर्गा पूजा के पंडाल पर हमले चिन्ता के बड़े कारण हैं, यह हिन्दू अस्तित्व एवं अस्मिता को कुचलने की साजिश एवं षडयंत्र है, जिस पर भारत सरकार को गंभीर होने के साथ इन पर नियंत्रण की ठोस कार्रवाई की अपेक्षा है। बीते अगस्त में शुरू हुई राजनीतिक उथल-पुथल के बीच शेख हसीना का प्रधानमंत्री पद से हटना और भारत आने के बाद बांग्लादेश में भारत विरोधी गतिविधियों को असामाजिक तत्वों व कट्टरपंथियों द्वारा हवा दिया जाना शर्मनाक एवं विडम्बनापूर्ण है। नई दिल्ली में बांग्लादेश के हिन्दू-अल्पसंख्यकों की सुरक्षा के प्रश्न को लेकर बार-बार चिंता तो व्यक्त की जा रही है, लेकिन करारा एवं सख्त संदेश देने की कोई कोशिश होती हुई नहीं दिख रही है। प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी एवं भाजपा सरकार के शासन में यदि ऐसी घटनाओं पर सख्ती नहीं बरती गयी तो फिर कब बरती जायेगी? यह विडंबना ही है कि नोबेल शांति पुरस्कार विजेता व कार्यवाहक रूप में सरकार के मुखिया का दायित्व निभा रहे मोहम्मद यूनुस के कार्यकाल में हिन्दुओं एवं हिंदू पहचान के प्रतीकों को निशाना बनाया जाना बदस्तूर रहना किसी अन्तर्राष्ट्रीय साजिश का हिस्सा हो सकता है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रमुख श्री मोहन भागवत ने नागपुर में विजयदशमी पर्व पर आयोजित रैली को सम्बोधित करते हुए हिन्दुओं पर हो रहे इन हमलों को लेकर बड़ा संदेश दिया है, अपेक्षा है सरकार भी जैसे को तैसे वाली स्थिति में आकर हिन्दुओं की रक्षा की सार्थक एवं प्रभावी पहल करें।

बांग्लादेश की आबादी में 7.95 फीसदी-सवा करोड़ से ज्यादा हिंदू शामिल हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान में हिंदुओं के खिलाफ जो कुचक्र रचे गये, उसी तरह की साजिश बांग्लादेश में सिर उठा रही है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पिछले दो महीने में बांग्लादेश के 52 जिलों में हिंदू समुदाय पर हमले की 200 से ज्यादा घटनाएं हुई। आज बांग्लादेश सांप्रदायिकता एवं कट्टरता की आग में झुलस रहा है। सांप्रदायिकता और धार्मिक कट्टरता लोकतंत्र के लिए सबसे बड़ा खतरा है। दोराहे पर खड़े बांग्लादेश में यह खतरा बढ़ता जा रहा है। खतरे की गंभीरता को देखते हुए वहां अंतरिम सरकार ने हिंदू मंदिरों, गिरजाघरों या अल्पसंख्यकों के किसी भी धार्मिक संस्थान पर हमलों की जानकारी देने के लिए हॉटलाइन शुरू की थी, लेकिन कितनी ही शिकायतें मिलने के बावजूद उन पर कार्रवाई का न होना, इनको लेकर मोहम्मद यूनुस सरकार का चुप्पी साधे रखना इस समस्या को गंभीर बना रहा है। बांग्लादेश के कट्टरपंथी वहां के हिंदुओं के लिए ही नहीं, भारत की सुरक्षा के लिए भी खतरा बन रहे हैं। इन हमलों एवं कट्टरतावादी शक्तियों का सक्रिय होना भारत एवं बांग्लादेश दोनों ही देशों के लिये खतरनाक है। कट्टरपंथियों के निरंकुश बने रहने से वहां की सरकार के इरादे और इच्छाशक्ति सवालों के घेरे में है।

भारत ने उचित तरीकों से ही इन घटनाओं को बेहद गंभीर बताते हुए इन पर न केवल चिंता जताई बल्कि अपनी आपत्ति भी दर्ज कराई। गौर करने की बात है कि अल्पसंख्यकों की सुरक्षा का यह मसला धीरे-धीरे दोनों देशों के रिश्तों में खटास घोलते हुए एक अहम फैक्टर बनता जा रहा है। दुर्गापूजा के पंडाल में बम फेंके जाने की खबर स्वाभाविक ही बांग्लादेशी हिंदू बिरादरी को सहमा एवं डरा देने वाली है। जेशोश्वरी मंदिर में मां काली के ताज की चोरी इस मायने में भी अहम है कि यह ताज 2021 में अपनी यात्रा के दौरान प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तोहफे के तौर पर दिया था। यही नहीं, गुरुवार को चटगांव में दुर्गापूजा के दौरान कुछ लोगों द्वारा जबरन इस्लामी क्रांति के गीत गाए जाने की भी खबर आई। ऐसे में भारत अगर इन घटनाओं के पीछे सुनियोजित साजिश की आशंका जता रहा है तो उसे निराधार नहीं कहा जा सकता। ऐसे में लगातार बिगड़ती स्थितियों में यूनुस और उनके सहयोगियों को शासन और कूटनीति से जुड़े गंभीर मसलों पर परिपक्वता दिखानी होगी। आंदोलन से जुड़े गैर जिम्मेदार तत्व अनाप-शनाप आरोप लगाएं तो कुछ हद तक समझा जा सकता है लेकिन अगर शासन में बैठे लोग भी इन तत्वों का समर्थन करते हुए दिखें तो उसे सही नहीं कहा जा सकता। यह एक अराजकता की स्थिति है।

बांग्लादेश में बद से बदतर हो रहे हालात एवं हिंदुओं पर लगातार हो रहे अत्याचार, उत्पीड़न, हमलों को लेकर संघ प्रमुख मोहन भागवत ने सावधान कर कोई गलत नहीं किया। सक्रिय, व्यवस्थित और संगठित होकर ही ऐसी नापाक एवं संकीर्ण मानसिकताओं का माकुल जबाव दिया जा सकता है। भागवत ने कहा, ''दुर्बल रहना अपराध है, हिंदू समाज को ये समझना चाहिए। अगर आप संगठित नहीं रहते हैं, तो आपको मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है।'' देश के दुश्मनों की ओर इशारा करते हुए मोहन भागवत ने कहा, ''भारत लगातार आगे बढ़ रहा है, लेकिन जब कोई भी देश जो आगे बढ़ रहा होता है तो उसकी राह में अडंगा लगाने वाले लोग भी बहुत सारे होते हैं। इसलिए दूसरे देशों की सरकारों को कमजोर करना दुनिया में चलता रहता है।' लेकिन किसी राष्ट्र को कमजोर करने के लिये हिंदुओं यानी अल्पसंख्यकों पर हमलों का सहारा लेना, उन्हें प्रोत्साहित करना विकृत एवं अराष्ट्रीय मानसिकता का द्योतक है।

वैसे भी बांग्लादेश का विकास भारत के सहयोग पर निर्भर है, जिस भू-भाग को रवींद्रनाथ टैगोर 'आमार सोनार बांग्ला' (मेरा स्वर्णिम बंगाल) कहते थे, जहां की अर्थ-व्यवस्था एवं अन्य विकास योजनाएं भारत के सहयोग से ही आगे बढ़ती रही है, कभी भारत की कोशिशों से ही बांग्लादेश अस्तित्व में आया था। बांग्लादेश को आधी से ज्यादा बिजली भारत से मिलती है। अनाज की बड़ी सप्लाई भी भारत से होती है। अगर भारत ने व्यापारिक संबंध तोड़ लिए तो बांग्लादेश की अर्थव्यवस्था चौपट हो सकती है। बावजूद इन सब स्थितियों के वहां भारत-विरोधी घटनाओं का उग्र से उग्रतर होना खुद के पांव पर कुल्हाड़ी चलाने जैसा है। बांग्लादेशी आकाओं को भगवान सद्बुद्धि दे। फिर भी अगर बांग्लादेश नहीं सुधरता है तो समय आ गया है कि हिंदुओं को निशाना बनाने की घटनाओं पर भारत कड़ा रुख अख्तियार करे। बांग्लादेश पर दबाव बनाने के साथ अंतरराष्ट्रीय मंचों पर इस मुद्दे को पुरजोर ढंग से उठाना चाहिए। इसके लिए कूटनीतिक प्रयास तेज करने की जरूरत है।

हिन्दू धर्म भारत की संस्कृति एवं आत्मा है। हिन्दू धर्म संयम, त्याग और बलिदान का धर्म है। इसमें हमेशा दूसरे धर्मों को सम्मान देने का काम किया है। हिन्दू धर्म उदारता, प्रेम, आपसी सद्भाव और सहनशीलता पर आधारित धर्म है। हिन्दू धर्म की सहिष्णुता को कमजोर मानकर हिन्दू धर्म की भावनाओं को ठेस पहुंचाने का कार्य लगातार होता रहा है। वैसे तो प्रत्येक धर्म की अपनी मान्यताएं होती हैं, किन्तु विकृत मानसिकता वाले लोगों ने हिन्दू धर्म को मध्यकाल से ही नीचा दिखाने की कोशिशें कीं। भारत पर लगातार आक्रांताओं के हमले होते रहे और बड़े पैमाने पर धर्मांतरण कराया गया। हिन्दुओं के लाखों मंदिर तोड़े गए। हिन्दुओं से अपने ही देश में हिन्दू होने पर 'जजिया' यानि कर लगाया गया। पूर्व की सरकारों ने भी वोट की राजनीति के चलते हिन्दुओं को दोयम दर्जा पर रखा। फिर भी हिन्दू धर्म ने उदारता और सहनशीलता को नहीं छोड़ा। अगर हिन्दू कट्टर होता तो अन्य धर्मों के लोग भारत में नहीं दिखते। देश बंटवारे के समय पाकिस्तान में 20 प्रतिशत से ज्यादा हिन्दू थे लेकिन आज उनकी आबादी 2 प्रतिशत भी नहीं रही और भारत में मुसलमानों की आबादी 2 प्रतिशत से 20 प्रतिशत नहीं होती। यह हिन्दू उदारता का ही परिणाम है। लेकिन प्रश्न है कि आखिर कब तक हिन्दू ऐसी अग्नि परीक्षा देता रहेगा? कब तक हिन्दू की सहिष्णुता को कमजोरी मानकर उन पर अत्याचार होते रहेंगे? कब तक हिन्दू शक्तिसम्पन्न होकर भी निर्बल बना रहेगा? इन सवालों के जबाव तलाशने होंगे वर्ना हिन्दुओं को अस्तित्वहीन करने की कोशिशें कामयाब होती रहेगी।

त्योहारों के सीजन में खाद्य विभाग चला रहा अभियान नापतोल विभाग भी मौके को लगा कैश करवाने में

इंदौर। त्योहार का मौसम आते ही सरकारी विभाग एकदम सक्रिय हो गए हैं। चाहे खाद्य एवं औषधि विभाग हो या नापतोल विभाग या अन्य कोई विभाग। हालांकि इसके पीछे कारण बताया जाता है कि लोगों को त्यौहार के समय खाद्य सामग्री शुद्ध एवं सही मिले लेकिन इसके पीछे कारण कुछ और ही होता है। सूत्र बताते हैं कि लोगों को सही वजन सही क्वालिटी और सही तोल बताना तो एक बहाना मात्र होता है इसके पीछे त्योहार के समय व्यापारी वर्ग से साथ ही बड़े कंपनियों से तगड़ी वसूली किया जाना भी एक बड़ा कारण है। यही वजह है कि वर्ष में 10 महीने कुंभकरण की नींद में सोया रहने वाले यह विभाग र रक्षाबंधन से दिवाली तक के त्योहारी सीजन में एकदम एक्टिव हो जाते हैं।

जानकारी अनुसार जहां एक ओर वर्तमान में खाद्य विभाग के अधिकारी सक्रिय हैं वहीं दूसरी ओर नापतोल विभाग के अधिकारी भी हरकत में दिखाई दे रहे हैं। खाद्य विभाग के अधिकारी जहां प्रतिदिन नकली मावा और अन्य खाद्य पदार्थ की जांच कर जप्त कर रहे हैं। इन अधिकारियों द्वारा लगातार कई दिनों से मीडिया को यह बताया जा रहा है कि उनके द्वारा इतनी कार्रवाई की जा रही है। ऐसे में यह प्रश्न उठता है कि क्या सिर्फ त्योहार के समय में ही नकली मावा और अशुद्ध खाद्य पदार्थ शहर में आते हैं। वर्ष के बाकी महीनों के दौरान खाद्य विभाग के अधिकारी कार्रवाई क्यों नहीं करते या सिर्फ त्योहार के समय ही खाद्य विभाग के अधिकारियों की नींद खुलती है। इसे दूसरे शब्दों में यूं भी कहा जा सकता है कि क्या त्योहारों के समय ही अधिकारी यो में भाई फैलाना चाहते हैं और कार्रवाई के नाम पर तगड़ी वसूली करना चाहते हैं। शायद यही कारण है कि हाल ही में 1000 किलो मावा जप्त कर लिया गया। हालांकि अभी उसकी रिपोर्ट आना बाकी है।

नापतोल विभाग भी उतरा बाजार में

ऐसा नहीं है कि सिर्फ खाद्य विभाग के अधिकारी ही खाद्य पदार्थों की जांच के लिए बाजारों में उतरे हो। दूसरी तरफ नापतोल विभाग भी बाजार में उतर चुका है। नापतोल विभाग के अधिकारियों ने भी होटल मिठाई की दुकान सहित अन्य व्यापारिक प्रतिष्ठानों पर जांच अभियान चलाया। बताया जाता है कि इस दौरान विभिन्न प्रकार के मामले सामने आए। इनमें एमआरपी नहीं लिखा होना और भी अन्य प्रकार के अनियमित पैकिंग फूड और अन्य सामानों पर दिखाई दी। इसके बाद नापतोल विभाग के अधिकारियों ने कई प्रकरण दर्ज किए हैं।

कई पैकिंग पदार्थ पर नहीं था यूनिट प्राइस

नापतोल विभाग के अधिकारियों के अनुसार जांच के दौरान यह पाया गया कि कई प्रकार के पैकिंग मैटेरियल पर सिंगल यूनिट प्राइस नहीं था। वही कई पैकेट ऐसे पाए गए जिम टोटल प्राइस तो लिखा था लेकिन पर केजी या पर ग्राम का प्राइस नहीं लिखा था, इस पर व्यापारी के विरुद्ध प्रकरण दर्ज किया गया है।

कलेक्टर आशीष सिंह ने जारी किए आदेश, तहसील कार्यालय के रीडरों को किया इधर से उधर

इंदौर। कलेक्टर आशीष सिंह ने विभिन्न तहसीलों और एसडीएम कार्यालय में पदस्थ रीडरों के तबादले का आदेश जारी किया है। प्रशासनिक कार्य में सुविधा का दावा किया गया है, लेकिन सूत्रों के अनुसार इसका कारण कुछ और हो सकता है। आदेश के अनुसार, राऊ तहसील कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 रवि राठौर को न्यायालय अपर कलेक्टर ज्योति शर्मा की कोर्ट में सहायक रीडर के रूप में पदस्थ किया गया है। इसी प्रकार, एसडीएम बिचोली हप्सी कार्यालय में सहायक ग्रेड 3 रामलाल गोरे को अपर कलेक्टर निशा डामोर की कोर्ट में सहायक रीडर बनाया गया है।

प्रभारी नायब तहसीलदार दयाराम निगम को खुड़ैल का प्रभारी नायब तहसीलदार बनाया गया, वहीं प्रभारी तहसीलदार भू-अभिलेख बलवीर सिंह राजपूत को हातोद तहसील का तहसीलदार नियुक्त किया गया है। सहायक ग्रेड 3 प्रवीण अवस्थी को समय अवधि पत्रों और अन्य इंद्राज कार्यों की जिम्मेदारी दी गई है।

सत्कार शाखा के स्टेनो टाइपिस्ट रामबाबू कोरी को अपर कलेक्टर निशा डामोर की कोर्ट में कंप्यूटर संबंधित कार्य का अतिरिक्त कार्यभार सौंपा गया है। सहायक ग्रेड 3 रोशनी रजक को समय अवधि पत्र शाखा का कार्य सौंपा गया है। सहायक अधीक्षक लोकेश आहूजा को अन्य आदेश जारी होने तक तहसील कार्यालय जूनी इंदौर में रखा गया है।

मास्टर प्लान की 23 सड़कों के लिए दूसरी बार में फर्म ने दिखाई रुचि

इंदौर। मास्टर प्लान के तहत बनने वाली शहर की 23 सड़कों का काम अगले महीने शुरू हो सकता है। जनकार्य विभाग द्वारा इसके लिए दूसरी बार जारी किए गए टेंडर में कुछ फर्मों ने इंटरेस्ट दिखाया है। बताया जाता है कि एक ही फॉर्म ने सभी 23 सड़कों के लिए टेंडर डाले हैं। संभावना जताई जा रही है कि निगम इसी फॉर्म को सभी 23 सड़कों का काम सौंप सकता है। हालांकि यह बताया जा रहा है कि इस बार पिछली बार के मुकाबले दो फीसदी रेट कम आए हैं। अब टेंडर खुलने के बाद अब निविदा समिति में मंजूरी के लिए भेजा जा रहा है। समिति से मंजूरी मिलने के बाद एमआईसी में प्रस्ताव मंजूरी के बाद जाएगा और यहां से स्वीकृति मिलते ही ठेकेदारों को वर्कऑर्डर जारी किया जाएगा। इस पूरी प्रकिया में करीब एक महीना लग जाएगा।

जानकारी अनुसार शहर में करीब 500 करोड़ रुपए लोकधन खर्च कर 23 सड़क बनाई जाना है। यह सभी सड़क मास्टर प्लान की हैं। इनके चार अलग-अलग पैकेज में टेंडर जनकार्य विभाग ने पिछले महीने में जारी किए। टेंडर आने के बाद तकनीकी के साथ फाइनेंशियल बिड खोली गई। इसमें सड़क बनाने के रेट ज्यादा आने पर 21 सितंबर को टेंडर निरस्त कर हाथोंहाथ दूसरी बार टेंडर रिकॉल कर दिए गए। दूसरी बार टेंडर जारी करने पर ठेकेदार की संख्या दो गुना हो गई, क्योंकि पहली बार में 8 टेंडर डले थे और दूसरी बार में 16 टेंडर आए। इन टेंडर की तकनीकी और फाइनेंशियल बिड खोल दी गई है। इसको लेकर जनकार्य विभाग के प्रभारी राजेंद्र राठौर का कहना है कि पिछली बार के टेंडर से इस बार 2 प्रतिशत तक रेट कम आए हैं। जिस ठेकेदार एजेंसी के रेट कम रहेंगे उसे ठेका दिया जाएगा। इसके साथ ही एक पैकेज में एक ही एजेंसी को काम मिलेगा। उन्होंने कहा कि जो रेट आए हैं उन्हें मंजूरी के लिए निविदा समिति में भेजा जा रहा है। समिति से मूंजरी मिलने के बाद एमआइसी में प्रस्ताव रख स्वीकृति दी जाएगी और फिर 23 सड़कों का काम शुरू होगा। उन्होंने कहा कि वर्क ऑर्डर जारी होने के बाद ठेकेदार एजेंसी को कम से कम ढाई वर्ष और अधिक से अधिक 4 वर्ष में काम पूरा करना होगा। निगम ने यह तय कर दिया।

निगमायुक्त ने विद्युत विभाग के इंजीनियरों को दिए निर्देश

दीपावली पर शहर की सभी स्ट्रीट लाइट रहें रोशन

इंदौर। दीपावली प्रकाश का पर्व है। जिस प्रकार लोग अपने घरों पर रोशनी करते हैं उसी प्रकार शहर में भी सड़कों पर पर्याप्त रोशनी होना चाहिए। कोशिश रहे शहर की कोई भी स्ट्रीट लाइट बंद ना हो। जो लाइटों में खराबी की शिकायतें हैं उन्हें तुरंत सुधारा जाए। रोशनी के पैरों पर चारों ओर स्ट्रीट लाइटों में भी रोशनी होना चाहिए। इस निर्देश निगमायुक्त ने विद्युत विभाग के उपयात्रियों को दिए हैं।

जानकारी अनुसार निगमायुक्त शिवम वर्मा ने निगम सीमा के सभी 22 झोनल कार्यालय पर पदस्थ विद्युत विभाग के उपयात्रियों को जिम्मेदारी सौंपी है कि दीपावली पर सड़कों की स्ट्रीट लाइट बंद नहीं होना चाहिए। बताया जाता है कि विद्युत विभाग के उपयंत्री को हर जोन की जिम्मेदारी सौंपी है। इसमें प्रत्येक वार्ड में स्ट्रीट लाइट की देखरेख के साथ-साथ दरोगा कर्मचारी व उपयंत्री की जिम्मेदारी होगी और इसमें लापरवाही मिलने पर कार्रवाई भी की जा सकती है। शहर के अधिकतर इलाकों में ज्यादातर स्ट्रीट लाइट बंद रहती है, लेकिन जहां कहीं भी खराबी हो वहां पर सुधार कार्य और इसके लिए विशेष तौर से निगम की तैयारी है और उस अनुसार काम भी हो रहा है।

मेंटेनेंस का सभी सामान करवा दिया उपलब्ध- अधिकारियों के अनुसार शहर में रात को रोशन होने वाली लाइट को लेकर अब सामग्री भी उपलब्ध कराई गई है। दरअसल सीएम हेल्पलाइन के साथ-साथ महापौर हेल्पलाइन में भी लगातार निगम को रोजाना 100 से अधिक बंद स्ट्रीट लाइट की शिकायत है।आज भी मिल रही है। यही कारण है कि अब निर्देश दिए गए हैं। स्ट्रीट लाइट को लेकर लगातार शिकायतों के कारण ही प्रत्येक झोन पर अधिकारियों की ड्यूटी लगाई दी गई है इसके अलावा शिकायत मिलने पर तुरंत ही सुधार का कार्य भी करने के लिए निर्देश दिए गए हैं। इसमें विशेष तौर से यह भी कहे जा रहा है कि लापरवाही बरतने पर तुरंत कार्रवाई भी की जा सकती है।

आईडीए छोड़ेगा स्कीम 171 की 151 हेक्टेयर जमीन, विज्ञप्ति जारी, अनुमति के लिए भटक रहे प्रॉपर्टी मालिकों को राहत

इंदौर। इंदौर विकास प्राधिकरण ने योजना क्रमांक 171 की जमीन छोड़ने के लिए विज्ञप्ति जारी कर दी है। इससे पुष्प विहार के 950 प्रॉपर्टी मालिकों को फायदा होगा। स्कीम में पुष्प विहार सहित कई कॉलोनियों के प्रॉपर्टी मालिक करीब 30 सालों से मकान बनाने के लिए भटक रहे हैं। योजना में शामिल होने के कारण प्रॉपर्टी मालिक को भवन निर्माण और अन्य अनुमतियां नहीं मिल पा रही थीं। पूरी योजना के मुक्त होने से करीब छह हजार प्रॉपर्टी मालिकों के सपने पूरे होंगे। आईडीए सीईओ आरपी अहिरवार ने बताया कि मंगलवार को विज्ञप्ति जारी कर दी गई है। योजना क्रमांक 171 में 151 हेक्टेयर जमीन शामिल है। इसमें 13 सोसायटियों और 211 लोगों की जमीन है।आईडीए को इससे 5 करोड़ 84 लाख रुपए लेने हैं। दो माह में राशि जमा करानी होगी।

मालव आँचल
इंदौर, 20 अक्टूबर से 26 अक्टूबर 2024

2020 के महत्वपूर्ण बिंदुओं पर मध्यप्रदेश में हो रहा बेहतर क्रियान्वयन

उच्च शिक्षा में उपयोगी नवाचार जारी रहे : मुख्यमंत्री डॉ. यादव

भोपाल। मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा है कि प्रदेश में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता का स्तर अन्य राज्यों की तुलना में बेहतर है। गुणवत्ता बनाए रखते हुए इसे और भी श्रेष्ठ बनाने के प्रयास किए जाएं। वर्ष 2021-22 में प्रदेश का सकल पंजीयन अनुपात 28.9 है जो राष्ट्रीय स्तर के सकल पंजीयन अनुपात 28.4 से अधिक है।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि मध्यप्रदेश में बहु विषयक दृष्टिकोण (मल्टी डिसप्लीनरी एप्रोच) के अंतर्गत एक लाख 25 हजार से अधिक विद्यार्थी अपने मूल विषयों के अलावा अन्य विषयों के अध्ययन का भी लाभ ले चुके हैं। निश्चित ही यह महत्वपूर्ण उपलब्धि है। उच्च शिक्षा में उपयोगी नवाचार जारी रखकर शिक्षा स्तर को ज्यादा बेहतर बनाने के प्रयास हों।

मुख्यमंत्री डॉ. यादव मंगलवार को समत्व भवन (मुख्यमंत्री निवास) में भारतीय ज्ञान परम्परा शीर्ष समिति और राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 टॉस्क फोर्स की बैठक की अध्यक्षता कर रहे थे। बैठक में उच्च शिक्षा मंत्री श्री इंदर सिंह परमार, टास्क फोर्स सदस्य अतुल कोठारी और म.प्र. हिंदी ग्रंथ अकादमी के अध्यक्ष श्री अशोक कड़ेल, मुख्यमंत्री कार्यालय में अपर मुख्य सचिव डॉ. राजेश राजौरा, प्रमुख सचिव उच्च शिक्षा अनुपम राजन, आयुक्त एवं सचिव उच्च शिक्षा श्री निशांत वरवड़े और समिति के सदस्यगण उपस्थित थे। राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के प्रमुख बिंदु बहुविषयक दृष्टिकोण में जहां कला संकाय के 18 हजार विद्यार्थियों ने वाणिज्य और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की, वहीं वाणिज्य संकाय के एक लाख से अधिक विद्यार्थियों ने कला और विज्ञान की शिक्षा प्राप्त की। मध्यप्रदेश में विज्ञान संकाय के ऐसे विद्यार्थियों की संख्या 11 हजार है, जिन्होंने कला और वाणिज्य विषय का चयन किया। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि राष्ट्रीय शिक्षा नीति के अनेक बिन्दुओं के क्रियान्वयन में मध्यप्रदेश अग्रणी राज्य है। उच्च शिक्षा व्यवस्था में स्नातक स्तर पर कृषि जैसे विषय के अध्ययन के प्रावधान के भी अच्छे परिणाम प्राप्त हुए हैं। सात विश्वविद्यालयों और 18 शासकीय स्वशासी महाविद्यालयों में बी.एससी कृषि पाठ्यक्रम का संचालन और एविएशन के सर्टिफिकेट कोर्स संचालक का 5 विश्वविद्यालयों में क्रियान्वयन हुआ है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव की अध्यक्षता में हुई बैठक में भारतीय ज्ञान परम्परा शीर्ष समिति के उपाध्यक्ष डॉ. अतुल कोठारी नई दिल्ली, समिति के सदस्य मध्यप्रदेश हिंदी ग्रंथ अकादमी के संचालक अशोक कड़ेल के अलावा उच्च शिक्षा टास्क फोर्स समिति के सदस्यों ने भागीदारी की। उल्लेखनीय है कि मध्यप्रदेश में उच्च शिक्षा क्षेत्र में गठित टास्क फोर्स समिति ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति - 2020 के क्रियान्वयन से संबंधित महत्वपूर्ण कार्रवाई का संपादन किया है। सदस्यों द्वारा महत्वपूर्ण सुझाव भी दिए गए हैं। विद्यार्थियों को उनकी रूचि, क्षमता, दक्षता और संसाधनों के अनुसार उच्च शिक्षा व्यवस्था से संबंधित कार्यवाहियां प्रदेश में सम्पन्न हुई हैं। बैठक में डॉ. आर.सी. कान्हेरे अध्यक्ष मध्यप्रदेश शुल्क विनियामक आयोग और विभिन्न विश्वविद्यालयों के कुलगुरूओं एवं शिक्षाविदों ने भागीदारी की।

प्रदेश में 19 लाख से अधिक विद्यार्थियों का डिजी लॉकर में पंजीयन

प्रदेश में 19 लाख 14 हजार 177 विद्यार्थियों ने डिजी लॉकर में पंजीयन करवाया है। बैठक में जानकारी दी गई कि प्रदेश के 6338 विद्यार्थियों ने 28 महाविद्यालयों में विभिन्न 90 प्रमाण पत्र पाठ्यक्रम पूर्ण किए हैं। प्रदेश में 35 महाविद्यालयों ने कॅरियर मेले लगाए, जिनमें 15 हजार 757 विद्यार्थियों को लाभान्वित किया गया। विभिन्न कम्पनियों ने 2276 विद्यार्थियों का प्रथम चरण में चयन भी किया है। प्रदेश में डिजिटल रिपोजीटरी की स्थापना की गई है। ई-शिक्षा इंट्रीगेटड पोर्टल का निर्माण भी किया गया है। शिक्षकों ने 1600 से अधिक ई-कंटेंट का निर्माण कर ई-शिक्षा पोर्टल पर अपलोड करने का कार्य किया है। फेकल्टी डेवलपमेंट प्रोग्राम से 4 हजार प्राध्यापकों को ऑनलाइन प्रशिक्षण दिया गया है।

एक छत्र के नीचे आएं समस्त विश्वविद्यालय

बैठक में प्राप्त सुझावों के संबंध में मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि यह महत्वपूर्ण सुझाव है कि समस्त विश्वविद्यालय एक छत्र के नीचे आएं। यह व्यवहारिक दृष्टि से आवश्यक है। विभिन्न विश्वविद्यालयों में पदों की पूर्ति और अन्य प्रशासनिक कार्यों के लिए अंततः उच्च शिक्षा विभाग का सहयोग ही अपेक्षित होता है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि इस संबंध में परीक्षण और विचारोपरांत आवश्यक निर्णय लिया जाएगा।

नर्सिंग पाठ्यक्रम भी चलाएं

मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने कहा कि महाविद्यालयों और विश्वविद्यालयों में पैरामेडिकल स्टॉफ की जरूरत के लिए नर्सिंग पाठ्यक्रम भी संचालित किए जाने का सुझाव भी विचार योग्य है। यह विद्यार्थियों, चिकित्सकों और आमजन के हित में है। बैठक में समिति और टॉस्क फोर्स के सदस्यों ने बताया कि मध्यप्रदेश में भारतीय विद्या (इंडोलॉजी) विभाग के साथ ही महापुरूषों की जीवनियों को पाठ्यक्रम का हिस्सा बनाने की पहल सराही गई है।

मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन से 12 हजार से अधिक को मिलेगी नौकरियां

भोपाल। महिला-बाल विकास मंत्री सुश्री निर्मला भूरिया ने जानकारी देते हुए बताया कि वर्तमान में प्रदेश में 84 हजार 659 आंगनवाड़ी केन्द्र और 12 हजार 670 मिनी आंगनवाड़ी केन्द्र संचालित हैं। प्रदेश में संचालित मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों का पूर्ण आंगनवाड़ी केन्द्रों के रूप में उन्नयन किये जाने का निर्णय मंत्रि-परिषद ने लिया है। मंत्री सुश्री भूरिया ने इस सौगात के लिये मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव का आभार माना है।

मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों के उन्नयन की आवश्यकता इसलिये थी कि आंगनवाड़ी केन्द्र में 6 वर्ष के बच्चों के मानसिक, शारीरिक एवं बौद्धिक विकास के लिये शाला पूर्व शिक्षा तथा कुपोषण निवारण के नवीन घटकों के दैनिक क्रियान्वयन के कारण मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता पर अतिरिक्त कार्य दायित्व के कारण आंगनवाड़ी सहायिकाओं की आवश्यकता भी जताई गई। मंत्री सुश्री भूरिया ने बताया कि मिनी आंगनवाड़ी केन्द्रों में एक मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता का प्रावधान था। अब इन केन्द्रों के उन्नयन के पश्चात मिनी आंगनवाड़ी कार्यकर्ता के स्थान पर एक पद आंगनवाड़ी कार्यकर्ता और एक पद आंगनवाड़ी सहायिका का होगा।

इसके अतिरिक्त उन्नयित 25 आंगनवाड़ी केन्द्रों पर एक पर्यवेक्षक के पद का प्रावधान है। इससे प्रदेश की कुल आंगनवाड़ी संख्या अनुसार पर्यवेक्षकों के 476 नवीन पद, 12 हजार 670 आंगनवाड़ी सहायिका सहित कुल 13 हजार 146 नवीन पद स्वीकृत किये जाने का निर्णय लिया गया है।

मध्यप्रदेश की बाग प्रिंट ने जापान में जीता दिल, मिली वैश्विक पहचान

भोपाल। धार जिले के बाग क्षेत्र की परंपरागत बाग प्रिंट हस्तकला ने एक बार फिर अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अपनी पहचान बनाने में सफलता हासिल की है। शिल्प गुरु और गोल्ड मेडलिस्ट मोहम्मद यूसुफ खत्री ने हाल ही में जापान में आयोजित कई कार्यक्रमों में मध्यप्रदेश की परंपरागत बाग प्रिंट की कला का प्रदर्शन किया, जिसने जापान के लोगों का दिल जीत लिया। इस कला के प्रति जापानियों की गहरी रुचि ने मध्यप्रदेश और भारत को गर्व का अवसर प्रदान किया है।

मोहम्मद यूसुफ खत्री, जो बाग प्रिंट हस्तशिल्प के पुश्तैनी कलाकार हैं, ने जापान के विभिन्न शहरों में बाग प्रिंट की मास्टर क्लासेस और कारीगरी का प्रदर्शन किया। 12 से 20 अक्टूबर 2024 के बीच ओसाका, क्योटो और साकाई जैसे प्रमुख शहरों में आयोजित कार्यक्रमों में उन्होंने जापान के लोगों को इस कला की बारीकियां सिखाईं। जापान में भारतीय राजदूत श्री सिबी जॉर्ज और वस्त्र मंत्रालय की विकास आयुक्त श्रीमती अमृत राज ने भी उनकी कला को सराहा। ओसाका से लगभग 40 किलोमीटर दूर कोबे में आयोजित 'इंडिया मेला' में तीन दिनों तक बाग प्रिंट कला का जीवंत प्रदर्शन किया गया। इस दौरान बच्चों और पर्यटकों ने बाग प्रिंट के गुर सीखे और गहरी दिलचस्पी दिखाई।

जापान में बाग प्रिंट की अनोखी पहचान – खत्री ने 16 अक्टूबर को वाकायामा शहर के म्यूज़ियम ऑफ मॉर्डन आर्ट में जाकर फाइन आर्ट के विद्यार्थियों और डेलीगेट्स को बाग प्रिंट की

विशेषताओं से अवगत कराया। इसके बाद 17 अक्टूबर को क्योटो के कोकोका क्योटो इंटरनेशनल कम्युनिटी हाउस में भी उन्होंने बाग प्रिंट की मास्टर क्लास ली। 20 अक्टूबर को साकाई शहर के मीना साकाई पार्क में उन्होंने स्थानीय लोगों को इस कला का प्रशिक्षण दिया, जिसे काफी सराहना मिली। प्रशिक्षण के दौरान लोगों ने बाग प्रिंट की तकनीक से रूमाल भी बनाए। इस दौरान खत्री ने बताया कि उन्होंने ओसाका से क्योटो का सफर बुलेट ट्रेन से किया, जो उनके लिए एक शानदार अनुभव था। जापान के लोगों ने बाग प्रिंट कला को न केवल पसंद किया, बल्कि इसके प्रति गहरी रुचि भी दिखाई। इससे यह स्पष्ट होता है कि भारतीय हस्तशिल्प को वैश्विक स्तर पर पहचान मिल रही है।

भारतीय महावाणिज्य दूतावास द्वारा आयोजन –15 अक्टूबर को भारत के प्रधान कोंसलावास, ओसाका-कोबे, जापान के महावाणिज्य दूत श्री चंद्रू अप्पार के निवास पर 'इंडिया भोज' का आयोजन किया गया। इस अवसर पर मोहम्मद यूसुफ खत्री ने महावाणिज्य दूत श्री चंद्रू अप्पार को बाग प्रिंट का स्टोल भेंट किया और उनकी कला की गहरी समझ के लिए प्रशंसा पाई। उन्होंने भारतीय महावाणिज्य दूतावास के कई अन्य अधिकारियों और कर्मचारियों को भी बाग प्रिंट के स्टोल भेंट किए ताकि वे इस कला की खूबसूरती को लंबे समय तक याद रखें।

मध्यप्रदेश का गौरव

मोहम्मद यूसुफ खत्री की जापान यात्रा ने न केवल बाग प्रिंट हस्तकला को वैश्विक मंच पर प्रमोट किया, बल्कि भारत और मध्यप्रदेश की सांस्कृतिक धरोहर को भी सम्मान दिलाया। उन्होंने जापान के भौगोलिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को ध्यान में रखते हुए आधुनिक और परंपरागत परिधानों को डिजाइन किया, जिन्हें जापानवासियों ने खूब सराहा। श्री खत्री, जो पहले भी बार्सिलोना, हेनोवर, बर्लिन, मिलान और कोलंबिया जैसे शहरों में अपनी कला का प्रदर्शन कर चुके हैं, ने कहा कि जापान में बाग प्रिंट को मिली अपार सफलता से वे अभिभूत हैं। उन्होंने भारत और मध्यप्रदेश सरकार को इस कला का असली संरक्षक मानते हुए आभार व्यक्त किया। इस आयोजन के तहत भारतीय महावाणिज्य दूतावास ने अतिथियों को जापान के विभिन्न सांस्कृतिक स्थलों का भ्रमण भी कराया, जिससे भारतीय शिल्पकारों को जापान की सांस्कृतिक समृद्धि को समझने का मौका मिला।

शराब की अवैध बिक्री को बर्दाश्त नहीं किया जाएगा-उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा

आबकारी विभाग को 16 हजार करोड़ रूपये का राजस्व लक्ष्य, व्यावसायियों के लिये हुई कार्यशाला

संगठित अपराध पर हो कड़ाई से कार्रवाई

भोपाल। *उप मुख्यमंत्री जगदीश देवड़ा ने कहा कि मध्यप्रदेश में शराब की अवैध बिक्री सख्ती से रोक लगाई जाए साथ संगठित अपराध पर कड़ी कारवाई की जानी चाहिए। श्री देवड़ा ने सोमवार को भोपाल स्थित पर्यावरण अध्ययन संस्थान (इप्को) में आयोजित नवीन आबकारी नीति/आबकारी व्यवस्था वर्ष 2025-26 के निर्धारण के संबंध में मदिरा की फुटकर बिक्री की दुकानों के लायसेंसियों की कार्यशाला में कही। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने आसवक एवं देशी/विदेशी मदिरा विनिर्माताओं एवं बार-लायसेंसियों के साथ भी बैठक की। श्री देवड़ा ने वाणिज्यक कर विभाग की उपलब्धियों को लेकर भी चर्चा की।*

उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने सभी विभागीय अधिकारियों को निर्देश दिये कि उनका कर्तव्य है कि अधिकारी अपने मुख्यालय पर रहकर अवैध कार्यो के प्रति सजग रहें। उन्होने कहा कि किसी भी परिस्थिति में मदिरा का अवैध परिवहन ना हो तथा संगठित अपराधियों के विरूद्व कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। प्रदेश में शराब के अवैध कारोबार पर पैनी नजर रखी जाएगी और जहां भी अवैध कारोबार या कालाबाजारी की सूचना मिलती है तो सख्त कार्रवाई की जाएगी।

उप मुख्यमंत्री ने कहा कि प्रदेश सरकार को राजस्व देने में वाणिज्यकर विभाग का महत्वपूर्ण योगदान है। वित्तीय वर्ष 2024-25 में आबकारी विभाग का राजस्व लक्ष्य 16 हजार करोड़ रूपये है। मुझे पूर्ण विश्वास है कि आप सभी के समन्वित प्रयास से यह लक्ष्य भी हम प्राप्त कर लेगें। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि वाणिज्यिक कर विभाग द्वारा निरन्तर नए-नए नवाचार किये जा रहें हैं। विभिन्न राज्यों की आबकारी नीति का अध्ययन किया जा रहा है। उनकी अच्छाईयों को प्रदेश की आबकारी नीति में संम्मिलित किया जाएगा। उन्होने कहा कि नीति

ठीक होगी जब अनुभवी लोगो से बात की जायेगी। कार्यशाला में प्रदेश के मदिरा व्यावसायियों एंव ठेकेदारों द्वारा उप मुख्यमंत्री को अपनी समस्या से भी अवगत कराया गया। उप मुख्यमंत्री श्री देवडा ने कहा कि अगर समस्या है तो उसका समाधान भी सरकार करेगी। कठिनाईयों को दूर किया जायेगा। सरकार बहुत सजग है। उन्होनें विभागीय अधिकारियों का निर्देश दिये कि प्रदेश के शराब व्यावसायियों की समस्या को हल करने का प्रयास करे। श्री देवड़ा ने कहा कि प्रदेश के राजस्व प्राप्ति में आबकारी विभाग का अहम भागीदारी रहती है।

कार्यशाला में उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि आबकारी विभाग के द्वारा ई-आबकारी पोर्टल के माध्यम से लायसेंसियों को अनेक सुविधाऐं प्रदान की गई हैं, जिससे अधिक पारदर्शिता के साथ कार्य सम्पादित किये जा रहें हैं तथा राजस्व में निरन्तर वृद्धि हो रही है। लायसेंसी भी नियमानुसार अपनी दुकान एवं बार का संचालन करें, विभाग द्वारा किसी प्रकार की गड़बड़ी होने पर लायसेंसियों के विरूद्ध भी कार्यवाही की जावेगी। उप मुख्यमंत्री श्री देवड़ा ने कहा कि विभागीय अधिकारियों से अपेक्षा है कि आप सभी जनप्रतिनिधियों/मंत्रियों/विधायकों के माध्यम से प्राप्त शिकायतों का त्वरित निराकरण करें एवं निराकरण के बाद संबंधित को अवगत भी कराया जाए। आबकारी अधिनियम का प्रभावी क्रियान्वयन कर आबकारी अपराधों पर रोक लगाना हम सभी का दायित्व है। सभी के समन्वित प्रयास से वर्ष 2025-26 के लिए संतुलित आबकारी नीति बनाना ही विभाग का लक्ष्य है। आशा करता हूं कि हम इसमें पूरी तरह सफल होगें। कार्यक्रम में प्रमुख सचिव वाणिज्यिक कर अमित राठौर ने कहा कि प्रदेश के राजस्व में मदिरा व्यावसायियों का बड़ा योगदान रहता है। उन्होने अपेक्षा कि जनता के स्वास्थ्य एवं सुरक्षा का ध्यान रखा जाना चाहिए। आबकारी आयुक्त अभिजीत अग्रवाल ने आभार व्यक्त किया।

देश को विश्व-गुरू बनाने में शिक्षक की अहम भूमिका-स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह

भोपाल। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री उदय प्रताप सिंह ने कहा है कि देश को विश्व-गुरू बनाने में शिक्षकों की महत्वपूर्ण भूमिका है। शिक्षकों के सहयोग के बगैर देश का विकास असंभव है। उन्होंने कहा कि शिक्षा विभाग में प्रशासनिक पदों की भर्ती शिक्षकों के माध्यम से होगी। प्रत्येक जिले में सीएम राइज स्कूलों की संख्या भी बढ़ाई जायेगी। स्कूल शिक्षा मंत्री श्री सिंह नरसिंहपुर जिले के गाडरवाड़ा में हुए राष्ट्रीय शिक्षा सम्मेलन और राज्य स्तरीय गिजुभाई शिक्षक सम्मान समारोह को संबोधित कर रहे थे। स्कूल शिक्षा मंत्री ने प्रदेश के 500 शिक्षक-शिक्षिकाओं को उनके उल्लेखनीय कार्य के लिये प्रशस्ति-पत्र एवं स्मृति चिन्ह भेंट कर सम्मानित किया। स्कूल शिक्षा मंत्री ने बताया कि भोपाल में जल्द ही प्रदेश से शिक्षकों को आमंत्रित कर संवाद किया जायेगा। उन्होंने कहा कि विभाग ने शिक्षकों के हितों को देखते हुए शिक्षकों को उच्च पद का प्रभार दिया गया है। प्रदेश में राज्य सरकार 40 करोड़ रूपये की लागत से निरंतर विभिन्न सीएम राइज स्कूल भवनों का निर्माण कर रही है। इन स्कूलों में विद्यार्थियों को विश्व स्तरीय सुविधा दी जायेगी। उन्होंने कहा कि यदि सभी शिक्षक नियमित तौर पर समय पर स्कूल पहुँचे तो निश्चित ही हमारी शिक्षण व्यवस्था की तस्वीर बदलेगी और बच्चों का भविष्य उज्ज्वल होगा।

नॉन के महाप्रबंधक अपनी जबावदेही समझे, लापरवाही पर होगी सख्त कार्रवाई : गोविंद सिंह राजपूत

नागरिक आपूर्ति निगम के संचालक मंडल की बैठक में खाद्य मंत्री ने अधिकारियों को दी हिदायत

भोपाल। खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण मंत्री गोविन्द सिंह राजपूत ने नागरिक आपूर्ति निगम के अफसरों को सख्त हिदायत दी है कि वो अपनी जबावदेही को समझें और अपने दायित्वों के निर्वहन में किसी भी प्रकार की लापरवाही न करें। जनहित से जुड़े किसी भी मामले में अधिकारियों कर्मचारियों द्वारा की गई तनिक गडबड़ी भी सहन नहीं की जाएगी। इन मामलों में अधिकारियों-कर्मचारियों की संलिप्तता सामने आने पर दोषी अधिकारियों- कर्मचारियों के खिलाफ कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। श्री राजपूत मध्यप्रदेश स्टेट सिविल सप्लाई कॉरपोरेशन लिमिटेड भोपाल की संचालक मंडल की बैठक को संबोधित कर रहे थे।

खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने मैदानी स्तर पर तथा मुख्यालय स्तर पर पदस्थ नागरिक आपूर्ति निगम के अधिकारियों-कर्मचारियों को दो टूक कहा कि निगम द्वारा व्यापक स्तर पर उपार्जन की कार्रवाई के साथ अन्य योजनाओं का क्रियान्वयन मैदान स्तर पर किया जा रहा है। इसमें कहीं कोई लापरवाही नहीं होनी चाहिये। खाद्य मंत्री श्री राजपूत ने कहा कि निगम को लाभ में लाने के लिये ठोस रणनीति बनायें। इसके लिये जरूरी हो तो अन्य राज्यों की पॉलिसी का भी अध्ययन करें।

कम्प्यूटर ऑपरेटरों को सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने 7 माह का समय

संचालक मंडल की बैठक में तय किया गया कि सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण करने के लिए संबंधित कंप्यूटर ऑपरेटरों को 7 माह की समय-सीमा दी जाये। जिन कम्प्यूटर ऑपरेटरों द्वारा सीपीसीटी परीक्षा उत्तीर्ण नहीं की गयी है, उन्हें अभी उच्च श्रमिक का वेतन दिया जाएगा। परीक्षा उत्तीर्ण करने पर उन्हें 17 हजार 500 का वेतन दिया जाएगा। इस निर्णय से 400 से ज्यादा कंप्यूटर ऑपरेटरों को लाभ मिलेगा।

उपार्जन में लगे कर्मचारियों को दी जाएगी प्रोत्साहन राशि

संचालक मंडल की बैठक में नॉन के समस्त अधिकारियों कर्मचारियों को 2023- 24 के उपार्जन कार्य हेतु सक्रिय योगदान के लिए 1 माह के मूल वेतन के बराबर प्रोत्साहन राशि के रूप में दिये जाने का निर्णय लिया गया है। नॉन के लगभग 800 अधिकारियों/कर्मचारियों को यह लाभ प्राप्त होगा। इसके लिए 3 करोड़ रूपये का प्रावधान किया गया है। बैठक में प्रमुख सचिव खाद्य, नागरिक आपूर्ति एवं उपभोक्ता संरक्षण श्रीमती रश्मि अरुण शमी, आयुक्त खाद्य सिवि चक्रवर्ती, एम.डी. नागरिक आपूर्ति निगम पी.एन. यादव और उप सचिव वित्त ओ.पी. गुप्ता सहित संचालक मंडल के अन्य सदस्यों ने महत्वपूर्ण सुझाव दिए।

BOLLYWOOD UPDATE

इन बॉलीवुड सितारों की पहली तनख्वाह जान उड़ जाएंगे होश

किसी भी शख्स के लिए पहली पगार बहुत मायने रखती है। चाहे वो कोई बड़ा सितारा हो या फिर आम आदमी, पहली सैलरी चाहे जितनी भी मिले, वो बहुत खास होती है। इस आर्टिकल में हम आपको बताने जा रहे हैं कि आपके फेवरेट सितारों को पहली सैलरी कितनी मिली थी। इस लिस्ट में सलमान खान से दीपिका पादुकोण तक जैसे सितारों का नाम भी शुमार है।

शाहरुख खान

बॉलीवुड के किंग शाह रुख खान ने अपने करियर की शुरुआत टीवी से की थी। मगर जब वह फिल्मों में आये तो वह लाखों दिलों की धड़कन बन गये। अभिनेता की पहली फिल्म दीवाना थी। आपको जानकर हैरानी होगी कि इस फिल्म के लिए अभिनेता ने अच्छी-खासी फीस ली थी। उन्हें पहली फिल्म के लिए 4 लाख रुपये फीस दी गई थी।

सलमान खान

सिनेमा के दबंग सलमान खान ने बतौर लीड हीरो करियर की शुरुआत फिल्म मैंने प्यार किया से की थी। इस फिल्म के लिए अभिनेता को 75 हजार रुपये फीस दी गई थी, लेकिन यह उनकी पहली सैलरी नहीं थी। जी हां, रेखा संग बीवी हो तो ऐसी के लिए सल्लू मियां ने पहली फीस कमाई थी, जो सिर्फ 11 हजार रुपये थी।

दीपिका पादुकोण

दीपिका पादुकोण आज सिनेमा की हाइएस्ट पेड एक्ट्रेसेज में से एक हैं, लेकिन क्या आपको पता है कि उन्होंने अपनी पहली फिल्म के लिए कितनी फीस वसूली थी। ग्रेपवाइन के मुताबिक, दीपिका ने शाह रुख खान स्टारर ओम शांति ओम के लिए एक रुपये तक नहीं वसूला था। उन्होंने पहली डेब्यू फिल्म फ्री में की थी।

अक्षय कुमार

अक्षय कुमार ने सौगंध मूवी से बॉलीवुड में डेब्यू किया था। इस फिल्म के लिए अभिनेता को सिर्फ 51 हजार रुपये पहली फीस मिली थी। आज अभिनेता एक-एक मूवी के करोड़ों चार्ज करते हैं।

अमिताभ बच्चन

फिल्मी दुनिया से कई बार रिजेक्ट होने के बाद अमिताभ बच्चन को साल 1969 में फिल्म सात हिंदुस्तानी से डेब्यू करने का मौका मिला था। इस फिल्म के लिए अभिनेता को 5 हजार रुपये पहली सैलरी मिली थी। आज 81 की उम्र में भी वह बॉलीवुड में धमाल मचा रहे हैं।

आमिर खान

बॉलीवुड के मिस्टर परफेक्शनिस्ट कहे जाने वाले आमिर खान की पहली सैलरी के बारे में पता है? थ्री इडियट्स, पीके जैसी ब्लॉकबस्टर फिल्में देने वाले अभिनेता ने 1988 में कयामत से कयामत तक से बॉलीवुड में कदम रखा था। उनकी पहली सैलरी 11 हजार रुपये थी।

शाहिद कपूर

बी-टाउन के हैंडसम हंक शाहिद कपूर की पहली फिल्म इश्क विश्क थी। इसी फिल्म से शाहिद बॉलीवुड में छा गये थे। इस फिल्म के लिए अभिनेता को डेढ़ लाख रुपये फीस मिली थी।

सन नियो के शो छठी मैया की बिटिया, इश्क़ जबरिया, साझा सिंदूर के कलाकारों ने साझा की अपनी धनतेरस की परंपरा

मुंबई। जैसे-जैसे धन और समृद्धि का त्यौहार धनतेरस नजदीक आ रहा है, सन नियो के लोकप्रिय शो के कलाकार जया भट्टाचार्य, लक्ष्य खुराना और साहिल उप्पल इस त्यौहार का महत्व और अपने व्यक्तिगत उत्सव के अनुभवों को साझा कर रहे हैं! जानिए, कैसे यह सितारे अपना धनतेरस का जश्न मनाते हैं।

सन नियो के शो छठी मैया की बिटिया में उर्मिला का किरदार निभा रही जया भट्टाचार्य ने धनतेरस को लेकर बड़े दिलचस्प अंदाज में अपनी भावनाएं साझा कीं। जब मैं बच्ची थी, तब मेरी मां हमेशा इस दिन बर्तन खरीदती थीं, क्योंकि यह हमारी परंपरा का हिस्सा था। अब मैं हर साल धनतेरस में कुछ खरीद कर अपने तरीके से इन परंपराओं का सम्मान करती हूं।÷

सन नियो के शो इश्क़ जबरिया में आदित्य की भूमिका निभाने वाले अभिनेता लक्ष्य खुराना ने अपने धनतेरस के अनुभव को साझा करते हुए कहा, ÷हर साल धनतेरस पर सोना खरीदना हमारे परिवार की खास परंपरा है, क्योंकि इसे बेहद शुभ माना जाता है।

सन नियो के शो साझा सिंदूर में गगन का किरदार निभा रहे साहिल उप्पल ने धनतेरस के प्रति अपनी भावनाएं साझा करते हुए कहा, ÷धनतेरस हमारे लिए बेहद खास दिन है, न सिर्फ इसकी शुभता के लिए, बल्कि इसलिए भी क्योंकि इसी दिन मेरी पत्नी का जन्म हुआ था।

छठी मैया की बिटिया शो वैष्णवी (बृंदा दहल द्वारा अभिनीत किरदार) की दिल छू लेने वाली कहानी बयां करता है, जो एक अनाथ होते हुए भी छठी मैया को अपनी मां मानती है। इश्क़ जबरिया शो में गुल्की (सिद्धि शर्मा द्वारा अभिनीत किरदार) की प्रेम और सपनों को पाने की संघर्षपूर्ण दास्तान प्रदर्शित की गई है, जो दर्शकों के दिलों को छू जाती है। वहीं, साझा सिंदूर में फूली (स्तुति विंकले द्वारा अभिनीत किरदार) की कहानी के इर्द-गिर्द घूमती है, जिसे उसके दूल्हे की शादी के दिन मृत्यु हो जाने के बाद अविवाहित विधवा करार दिया जाता है।

देखिए छठी मैया की बिटिया, इश्क़ जबरिया, और साझा सिंदूर हर सोमवार से शनिवार, शाम 7:00, 7:30 और 8:00 बजे सिर्फ सन नियो पर।

वायु प्रदूषण से बचने के लिए रोज करें ये 5 योगासन

वायु प्रदूषण एक बढ़ती समस्या है, जो हमारे स्वास्थ्य, खासकर हमारे फेफड़ों को गंभीर रूप से प्रभावित करती है। सर्दी का मौसम करीब आने के साथ-साथ हवा की गुणवत्ता बिगड़ने लगती है। पराली और पटाखों से निकलने वाला धुंआ, दिल्ली-एनसीआर की हवा का AQI काफी बढ़ा देता है, जिसके कारण सांस लेना दूभर हो जाता है। इसके अलावा, आंखों में जलन, खले में खराश और खांसी जैसी कई परेशानियां भी होती हैं। हालांकि, इसका सबसे ज्यादा असर हमारे फेफड़ों पर ही होता है। इसलिए जरूरी है कि हम अपने फेफड़ों का ख्याल रखें, ताकि हवा में मौजूद प्रदूषण के कारण हमारे फेफड़ों को कम से कम नुकसान पहुंचे। यहां हम फेफड़ों को मजबूत बनाने के लिए कुछ योगासन बताने वाले हैं। इन योगासनों की मदद से फेफड़े मजबूत बनते हैं और सांस लेने की क्षमता बढ़ती है। आइए जानें इन 5 योगासनों के बारे में।

अनुलोम-विलोम प्राणायाम के फायदे- यह प्राणायाम फेफड़ों की काम करने की क्षमता को बढ़ाता है, तनाव कम करता है और मन को शांत करता है।

भस्त्रिका प्राणायाम

कैसे करें- इस प्राणायाम में तेजी से और गहरी सांस लेना और छोड़ना शामिल है।

फायदे- यह प्राणायाम फेफड़ों को ऑक्सीजन से भरता है, ब्लड सर्कुलेशन को बेहतर बनाता है और शरीर को डिटॉक्स करता है।

कपालभाति प्राणायाम

कैसे करें- इस प्राणायाम में पेट को अंदर की ओर खींचते हुए तेजी से सांस छोड़ना शामिल है।

फायदे- यह प्राणायाम फेफड़ों को मजबूत बनाता है, पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है और तनाव कम करता है।

भुजंगासन (कोबरा पोज)

कैसे करें- पेट के बल लेटकर, हाथों को कंधों के नीचे रखकर शरीर को ऊपर उठाएं।

फायदे- यह आसन फेफड़ों को खोलता है, रीढ़ की हड्डी को मजबूत बनाता है और पाचन तंत्र को बेहतर बनाता है।

त्रिकोणासन (त्रिकोण पोज)

कैसे करें- पैरों को चौड़ा करके खड़े हो जाएं और एक पैर को बाहर की ओर मोड़ें। हाथों को ऊपर उठाएं और एक हाथ को जमीन पर रखें।

फायदे- यह आसन फेफड़ों को खोलता है, शरीर को लचीला बनाता है और तनाव कम करता है।

अनुलोम-विलोम प्राणायाम

कैसे करें- इस प्राणायाम में दाएं नासिका से सांस लेना और बाएं नासिका से छोड़ना शामिल है। फिर इसी प्रक्रिया को उल्टी तरफ से दोहराना होता है।

योग करने से साथ-साथ इन बातों का भी रखें ध्यान

मास्क पहनें- घर से बाहर निकलने से पहले हमेशा मास्क पहनें। खासकर ज्यादा प्रदूषित क्षेत्रों में।

घर के अंदर हवा को शुद्ध करें- एयर प्यूरीफायर का इस्तेमाल करें। घर की खिड़की-दरवाजों पर पर्दे लगाएं और उन्हें नियमित रूप से साफ करें।

पौधे लगाएं- पौधे हवा को शुद्ध करते हैं। इसलिए अपने घर के भीतर भी इंडोर प्लांट्स लगा सकते हैं।

हेल्दी डाइट लें- विटामिन और मिनरल से भरपूर डाइट लें।

पर्याप्त नींद लें- नींद शरीर को स्वस्थ रखने के लिए जरूरी है।

छिलके वाली मूंग दाल एक साथ करती है कई बीमारियों पर वार

मूंग दाल को भरपूर पोषक तत्वों के कारण सुपर फूड कहा जाता है। इसका सेवन करने से सेहत से जुड़े कई फायदे मिलते हैं। इसमें कैलोरी कम और फाइबर, विटामिन बी, विटामिन सी और के की मात्रा ज्यादा होती है। एंटीऑक्सीडेंट से भरपूर यह दाल ऑक्सीजन के स्तर को बढ़ाकर शरीर को डिटॉक्स करने में मदद करती है। इसमें में प्रचुर मात्रा में फाइबर, प्रोटीन, फास्फोरस, मैग्नीशियम, पोटेशियम, आयरन, विटामिन बी 6 पाया जाता है। ये सभी पोषक तत्व बेहतरीन सेहत के लिए जरूरी होते हैं।

इन परेशानियों में कारगर

वजन घटाने में फायदेमंद- अगर आप अपने बढ़त वजन से परेशान हैं तो मूंग दाल का सेवन शुरू करें। यह लो कैलोरी युक्त फ़ूड वजन तेजी से कम कर सकते हैं। इसमें मौजूद प्रोटीन और फाइबर पेट को फूल रखते हैं जिससे जल्दी भूख नहीं लगती है।

पाचन करे बेहतर- अगर खाना जल्दी नहीं पचता है तो मूंग दाल आपको इस समस्या से छुटकारा दिला सकती है। मूंग दाल में मौजूद फाइबर खाना को पचाने में मदद करता है।

आंखों के लिए फायदेमंद-विटामिन ए से भरपूर मूंग दाल आंखों की रौशनी की बढ़ाती है। अगर आपके आंखों की रौशनी कमजोर हो गई है तो उसे तेज करने के लिए इस दाल का सेवन रोजाना करें।

पेट के लिए लाभकारी- यह दाल पेट की समस्या से जूझ रहे लोगों के लिए लाभकारी है। जिन लोगों को एसिडिटी, अपच और ब्लोटिंग की समस्या ज़्यादा होती है। उन्हें डाइट में मूंग दाल को ज़रूर शामिल करना चाहिए। यह दाल एसिड के स्तर को कम कर, शरीर के पीएच स्तर को रेगुलर करने में मदद करता है।

इम्यूनिटी करे बूस्ट-अगर इम्यूनिटी कमजोर है तो डाइट में मूंग दाल शामिल करें। इसमें भरपूर मात्रा में विटामिन सी पायी जाती है। इस दाल के सेवन से रोग प्रतिरोधक क्षमता तेजी से बढ़ेगी और मौसमी बीमारियों का खतरा महसूस नहीं होगा।

कब करें और कैसे करें सेवन

मूंग का सेवन आप दाल के रूप में कर सकते हैं। साथ ही आप अगर इसे अंकुरित कर कच्चा या उबाल कर कहते हैं तब भी बहुत ज़्यादा फायदा मिलेगा। अंकुरित दाल का सेवन सुबह नाश्ते के रूप में कर सकते हैं।

बर्थडे केक हो सकते हैं सेहत के लिए खतरनाक

केक, बर्थडे पार्टी हो, शादी हो या फिर फेयरवेल पार्टी हो हर खास मौके का एक अहम हिस्सा बन चुका है। अपने मनपसंद फ्लेवर और खूबसूरत डेकोरेशन के साथ केक हर सेलिब्रेशन को और भी खास बना देता है। आजकल लोग हर छोटे से लेकर बड़े सेलिब्रेशन में केक जरूर कट करते हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि आपके इस खास बर्थडे केक में छुपे कुछ ऐसे तत्व होते हैं, जो कैंसर का खतरा बढ़ा सकते हैं।

शायद यह आपने कभी भी नहीं सोचा होगा कि केक खाने से कैंसर का खतरा बढ़ सकता है। विशेषज्ञों की माने तो कुछ केक में इस्तेमाल होने वाली सामग्रियां कैंसर जैसी गंभीर बीमारियों का कारण बन सकती हैं। केक बनाने में जिन रंगों का इस्तेमाल किया जाता है वे स्वास्थ्य के लिए बेहद नुकसानदायक होते हैं। इसलिए अगर आप अगली बार जब भी केक खाएं, तो केक का चयन बड़ी

ही सावधानी से करें।

क्यों है केक नुकसानदायक

एक्सपर्ट का कहना है कि बर्थडे केक में मौजूद आर्टिफिशियल फूड कलर केक को दिखने में तो खूबसूरत बनाते हैं। लेकिन, असल में ये आपको बीमार कर सकते हैं।

ये सिंथेटिक कलर खासकर, लाल, पीले और नीले रंग, कार्सिनोजन इफेक्ट पैदा करते हैं और कैंसर का कारण बन सकते हैं।

यह आर्टिफिशियल कलर, बच्चों में हाइपरएक्टिविटी को बढ़ा सकते हैं और इनमें कार्सिनोजन कंपाउड होते हैं। इस तरह के रंग, आमतौर पर पेट्रोलियम बेस्ड होते हैं। इनका लंबे समय तक इस्तेमाल कई बीमारियों का कारण बन सकता है।

इसके अलावा, केक में शुगर भी बहुत अधिक मात्रा में होती है। अधिक शुगर खाने से मोटापा, डायबिटीज और कई तरह के कैंसर का खतरा बढ़ता है।

शुगर लेवल बढ़ने पर, इंसुलिन का प्रोडक्शन बढ़ जाता है। यह कैंसर सेल्स की ग्रोथ को बढ़ा सकता है। शुगर की वजह से शरीर में इंफ्लेमेशन बढ़ने लगता है और इसके कारण कैंसर समेत कई अन्य क्रॉनिक डिजीज का खतरा बढ़ जाता है।

यह आर्टिफिशियल कलर केक को आकर्षक और रंगीन जरूर बनाते हैं। लेकिन इनका लगातार सेवन कई स्वास्थ्य समस्याओं का कारण बन सकता है।

केक को लंबे समय तक फ्रेश बनाए रखने में इस्तेमाल किए जाने वाले प्रिजर्वेटिव की वजह से भी सेहत को खतरा हो सकता है। इन प्रिजर्वेटिव्स में बीएचए और बीएचटी शामिल हैं। ये कैंसर की वजह बन सकते हैं।

एक्सपर्ट का कहना है कि कभी-कभार अगर आप कम मात्रा में केक खाएं, तो इससे आमतौर पर कोई खतरा नहीं होता है। लेकिन, लंबे समय तक और अधिक मात्रा में इसका सेवन कैंसर के खतरे को बढ़ा सकता है।

इसकी जगह आप घर पर बनी हेल्दी चीजों को डाइट में शामिल करें, जिससे सेहत बनी रहे।

राष्ट्रपति मुर्मु ने इंदौर को 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से किया सम्मानित

मुख्यमंत्री डॉ . यादव ने जल-संरक्षण में अग्रणी बनने पर इंदौर को दी बधाई

इंदौर। राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से पश्चिम जोन के अंतर्गत इंदौर को सर्वश्रेष्ठ जिले के तौर पर पुरस्कृत करने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने इस उपलब्धि के लिए समस्त प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा है कि मध्यप्रदेश पानी की एक-एक बूंद के उचित उपयोग एवं संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और जल-संरक्षण की दिशा में निरंतर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भली-भाँति समझते हुए हमने प्रदेश में जल-संरचनाओं का जाल बिछाया है, पुरानी जल-संरचनाओं का नवीनीकरण किया है और सिंचाई क्षमता को बढ़ाने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा है।

इंदौर जिले में जल-संरक्षण के क्षेत्र में महत्वपूर्ण उपलब्धियां हासिल की गई हैं। जिले में अजनार, बालम, चोरल, कराम, मोरल और पातालपानी नदियों के जलग्रहण क्षेत्रों में विभिन्न कार्य किए गए हैं, जिनमें 366 पौध-रोपण कार्य, 216 जल-संचयन कार्य, 60 रिचार्ज संरचनाएं, 90 वाटरशेड उपचार कार्य और 814 जल और मिट्टी संरक्षण कार्य शामिल हैं। इसके अलावा बालम नदी के जलग्रह-क्षेत्र में 5 अमृत सरोवर, 4 फार्म पॉन्ड, 5 चेक डैम और 30 गेबियन जाल संरचनाएं बनाई गई हैं।

जिले में वृहद स्तर पर जल-संचयन संरचनाएं भी निर्मित की गयी हैं, जिसमे 420 फार्म पॉन्ड, 180 पेरकोलेशन टैंक, 100 निस्तारी टैंक और 190 चेक डैम शामिल हैं। इससे जिले में जल-भंडारण क्षमता में 30 लाख घन मीटर की वृद्धि हुई है। लगभग 25

हजार 500 हेक्टेयर क्षेत्र को ड्रिप और स्प्रिंकलर सिंचाई प्रणालियों के तहत लाया गया है, जिससे जिले के लगभग 16 हजार किसान लाभान्वित हुए हैं।

जिले में एक लाख घरों की छतों पर नागरिकों द्वारा अपने खर्च पर ही वर्षा जल संचयन प्रणाली स्थापित की गई हैं और 10 स्थानों पर पीज़ोमीटर लगाए गए हैं, जिससे जल स्तर का मूल्यांकन किया जा सके। हरियाली महोत्सव के दौरान 20 लाख पौधे लगाए गए और इंदौर शहरी क्षेत्र में 2 लाख 55 हजार पौधे लगाए गए हैं।

राष्ट्रीय जल पुरस्कारों का उद्देश्य पानी के महत्व के बारे में जागरूकता उत्पन्न करना और स्वच्छ जल के उपयोग के सर्वोत्तम प्रचलन अपनाने के लिए प्रेरित करना है। 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार में सर्वश्रेष्ठ राज्य, सर्वश्रेष्ठ जिला, सर्वश्रेष्ठ ग्राम पंचायत, सर्वश्रेष्ठ शहरी स्थानीय निकाय, सर्वश्रेष्ठ स्कूल या कॉलेज, सर्वश्रेष्ठ उद्योग, सर्वश्रेष्ठ जल उपयोगकर्ता संघ, सर्वश्रेष्ठ संस्थान और सर्वश्रेष्ठ नागरिक समाज सहित 9 श्रेणियों में संयुक्त विजेताओं सहित 38 विजेताओं को पुरस्कृत किया गया है।

पुराने तालाबों का भी किया गया जीर्णोद्धार

जल-संचयन के प्रयासों के अंतर्गत नाला ट्रेंचिंग (गहरीकरण) के लगभग 420 कार्य किए गए हैं, जिससे जल स्तर में वृद्धि हुई है। पुष्कर धरोहर समृद्धि अभियान के तहत 462 पुरानी संरचनाएं जैसे- तालाब, चेक डैम और स्टॉप डैम का जीर्णोद्धार किया गया है, जिससे जल-भंडारण क्षमता में 16 लाख घन मीटर की वृद्धि हुई है और 1500 हेक्टेयर कृषि भूमि के लिए अतिरिक्त सिंचाई सुविधा उपलब्ध हुई है।

कलेक्टर इंदौर आशीष ने प्राप्त किया पुरस्कार : विज्ञान भवन दिल्ली में हुआ कार्यक्रम

उल्लेखनीय है कि इंदौर जिले को जल-संचयन और जल-संरक्षण में महत्वपूर्ण योगदान के लिए पश्चिम क्षेत्र के सर्वश्रेष्ठ जिले का राष्ट्रीय जल पुरस्कार से सम्मानित किया गया है। दिल्ली स्थित विज्ञान भवन में हुए 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार-2023 समारोह में राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु ने यह पुरस्कार प्रदान किया। कार्यक्रम में केंद्रीय जल शक्ति मंत्री श्री सी.आर. पाटिल और राज्यमंत्री श्री वी. सोमन्ना भी उपस्थित थे। पुरस्कार इंदौर के कलेक्टर श्री आशीष सिंह, नगर निगम आयुक्त श्री शिवम वर्मा तथा जिला पंचायत सीईओ श्री सिद्धार्थ जैन ने ग्रहण किया।

इंदौर को 5वाँ राष्ट्रीय जल पुरस्कार प्राप्त होने पर मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने दी बधाई

राष्ट्रपति श्रीमती द्रौपदी मुर्मु द्वारा 5वें राष्ट्रीय जल पुरस्कार से पश्चिम जोन के अंतर्गत इंदौर को सर्वश्रेष्ठ जिले के तौर पर पुरस्कृत करने पर मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने जल संरक्षण की दिशा में इस उपलब्धि के लिए समस्त प्रदेशवासियों को बधाई दी है। मुख्यमंत्री डॉ. यादव ने सोशल मीडिया पर जारी संदेश में लिखा है कि - मध्यप्रदेश पानी की एक-एक बूंद के उचित उपयोग एवं संरक्षण के लिए प्रतिबद्ध है और जल संरक्षण की दिशा में निरंतर अपनी भूमिका का निर्वाह कर रहा है। आने वाली पीढ़ी के लिए अपनी नैतिक जिम्मेदारी को भलीभाँति समझते हुए हमने प्रदेश में जल-संरचनाओं का जाल बिछाया है, पुरानी जल-संरचनाओं का नवीनीकरण किया है और सिंचाई क्षमता को बढ़ाने का लगातार प्रयत्न किया जा रहा है।

पश्चिम मप्र में जारी वित्तीय वर्ष में 1568 करोड़ यूनिट बिजली वितरित

पिछले वित्तीय वर्ष की तुलना में 74 करोड़ यूनिट ज्यादा आपूर्ति

इंदौर। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपनी इंदौर की प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि कंपनी क्षेत्र के इंदौर एवं उज्जैन राजस्व संभागीय क्षेत्र के सभी 15 जिलों में राज्य शासन के आदेशानुसार गुणवत्ता के साथ बिजली आपूर्ति सुनिश्चित की जा रही है। शासन के अनुसार कृषि क्षेत्र के लिए दैनिक दस घंटे एवं अन्य सभी क्षेत्र के लिए चौबीस घंटे आपूर्ति व्यवस्था लागू हैं। उन्होंने बताया कि जारी वित्तीय वर्ष में अब तक 1568 करोड़ यूनिट बिजली आपूर्ति हो चुकी है, समान अवधि में गत वर्ष आपूर्ति 1494 करोड़ यूनिट थी। प्रबंध निदेशक ने बताया कि सबसे ज्यादा बिजली आपूर्ति इंदौर शहर वृत्त एवं इंदौर ग्रामीण वृत्त के अधीन हुआ है। इंदौर वृत्त के अंतर्गत करीब 232 करोड़ यूनिट बिजली वितरित हुई है, ग्रामीण वृत्त सीमा में 269 करोड़ यूनिट आपूर्ति हुई। प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने बताया कि उज्जैन वृत्त में 148 करोड़ यूनिट, खरगोन में 141 करोड़ यूनिट, देवास में 130 करोड़ यूनिट धार वृत्त में 110 करोड़ यूनिट बिजली आपूर्ति हुई है।

सीखो कमाओ योजना में अब सेल्फ़ी के बाद दर्ज होगी अटैंडेंस

गड़बड़ी की शिकायतें मिलने के बाद सरकार ने किया एप अपडेट

***इंदौर।** सीखो कमाओ योजना में भी गड़बड़ी की शिकायतें सामने आई है। बताया जा रहा है कि काम करने वाले मनमर्जी के अनुसार उपस्थित दर्शा रहे। इसे दूर करने के लिए अब सरकार ने सीखो कमाओ योजना के तहत जिस ऐप से हाजिरी भरी जाती है उसे अपडेट किया है। योजना के तहत अब काम करने वालों को पहले सेल्फी मोड पर फोटो देना होगा उसके बाद उपस्थिति दर्ज की जाएगी।*

जानकारी अनुसार इस योजना में 7 घंटे कार्य करने के बाद व्यक्ति को 10 हजार के लगभग स्टाइपेंड दिया जाना है। कौशल विकास व रोजगार के उद्देश्य से योजना लागू हुई, लेकिन इसमें फर्जीवाड़ा शुरू हो गया। गड़बड़ी रोकने के लिए अब सरकार ने ऐप को अपग्रेड कर प्रतिदिन फेस रजिस्ट्रेशन करना जरूरी कर दिया है।कौशल विकास केंद्र की देखरेख में मुख्यमंत्री सीखो - कमाओ योजना में अंडर ग्रेजुएट को 8 हजार व ग्रेजुएट को 10 हजार रुपए प्रतिमाह स्टाइपेंड दिया जा रहा था। कोई भी एजेंसी काम देती है तो उसके वेतन में क्रमशः 8 व 10 हजार का योगदान सरकार का होता है। उद्देश्य है कि युवाओं को काम करते हुए दक्ष बनाया जाए। प्रदेश में करीब 84 हजार पद इसमें शामिल थे। सरकार ने ऐप बनाया था, जिसमें अभ्यर्थी को प्रतिदिन न्यूनतम 7 घंटे की उपस्थिति पर स्टाइपेंड जारी होता है। सरकार को पता चला कि स्टाइपेंड के लिए उपस्थिति में फर्जीवाड़ा किया जा रहा है। अभ्यर्थी 7 घंटे काम नहीं करते हैं। एक साल बाद मोबाइल ऐप को अपडेट किया गया है।

इसके तहत मोबाइल ऐप पर अभ्यर्थी को पहले फेस रजिस्ट्रेशन करना है। यानी सेल्फी मोड पर फोटो अपलोड करना है। इसके बाद उपस्थिति दर्ज करना 7 योजना प्रभारी आईटीआई प्राचार्य जीएस शाजापुरकर के मुताबिक, योजना में गड़बड़ी की बात सामने आई थी। इसके बाद हर दिन फेस रजिस्ट्रेशन शुरू किया गया है।

अब उड़न दस्ते सुधारेंगे सरकारी कॉलेजों में शिक्षा का स्तर

इंदौर। सरकारी कॉलेज में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए अब उड़नदस्ते का गठन किया जाएगा। इसके सदस्य हर सरकारी कॉलेज में करवाई जा रही पढ़ाई का स्तर जचने के लिए दौरा करेंगे और अपनी रिपोर्ट यूनिवर्सिटी कुलसचिव को सौंपेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि उड़न दस्ते के सदस्य न सिर्फ समस्या यूनिवर्सिटी को बताएंगे बल्कि उसका समाधान भी कॉलेज स्तर पर ही प्रस्तुत करेंगे।

जानकारी अनुसार हाल ही में उच्च शिक्षा विभाग की कुलसचिवों के साथ हुई बैठक में यह निर्देश दिए हैं। इसमें कहा गया है कि

उच्च शिक्षा विभाग ने समीक्षा बैठक में दिए निर्देश

कॉलेजों में शिक्षा का स्तर सुधारने के लिए समीक्षा की जा रही है। इसमें आ रही परेशानी को देखते हुए उड़नदस्ते का गठन करने का निर्णय लिया है।इसका गठन कुलसचिव विवि के प्रोफेसर के साथ मिलकर करेंगे। उड़नदस्ता नकल रोकने वाले दल की तरह किसी कॉलेज में नहीं पहुंचेगा, बल्कि यह प्रबंधन को पहले सूचना देगा। फिर वहां पर उपलब्ध साधनों और पढ़ाई की गुणवत्ता की जांच करेगा। शोध केंद्रों और वहां की लाइब्रेरी आदि की भी जांच करेगा।इसका उद्देश्य सिर्फ कॉलेजों की परेशानी को उजागर करना ही नहीं रहेगा। दल वहां की समस्या का समाधान भी विवि को देगा ताकि शिक्षा का स्तर अपग्रेड हो सके। वहीं पीएम श्री कॉलेज के निरीक्षण के लिए सीनियर प्रोफेसर की मदद ली जा सकती है। कुलसचिव को निर्देश दिए हैं कि प्रोफेसर की कमी को देखते हुए प्रतिनियुक्ति की प्रथा को शिथिल करके, शासन के निर्देश अनुसार पदों को भरने का काम करे ताकि पढ़ाई की गुणवत्ता प्रभावित नहीं हो।

स्मार्ट मीटर परियोजना की गतिशीलता के लिए एनएबीएल स्तर की टेस्टिंग

मीटर परीक्षण क्षमता में तेजी से की जाएगी बढ़ोत्तरी- प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह

इंदौर। स्मार्ट मीटर परियोजना केंद्र एवं राज्य शासन की सर्वोच्च प्राथमिकता वाली है। इसके लिए हर संभव प्रयास कर गुणवत्ता, समय पालन और परीक्षण का कार्य किया जाएगा। पश्चिम क्षेत्र कंपनी में भी मीटर टेस्टिंग का कार्य एनएबीएल स्तर से हो रहा है। मीटर परीक्षण क्षमता में तेजी से वृद्धि की जाएगी। मध्यप्रदेश पश्चिम क्षेत्र विद्युत वितरण कंपन की प्रबंध निदेशक सुश्री रजनी सिंह ने ये विचार व्यक्त किए। मंगलवार की शाम पोलोग्राउंड इंदौर स्थित न्यू एलटीएमटी लेब का निरीक्षण करते समय उन्होंने कहा कि अभी करीब आठ लाख स्मार्ट मीटर लगे है, इससे दुगुनी संख्या में और लगाए जाना है।

प्रकाशक, मुद्रक एवं स्वामी जयश्री जैन द्वारा अपनी दुनिया प्रिंटर्स 13, प्रेस कॉम्प्लेक्स ए.बी. रोड इंदौर से मुद्रित एवं 22, प्रेस काम्पलेक्स, प्रेस हाऊस, ए.बी. रोड इंदौर 452008 से प्रकाशित। प्रधान संपादक- डॉ. राजेश जैन, मो. 9425322301 (डाक पंजीयन MP/IDC/1462/2016-2019)